

लगा दिया गया है। (दोस्रिये परिशिष्ट ३. अनुबन्ध संख्या ११३)। जुलाई १९५७ के घन्त तक जो शाखाएं खुल चुकी हैं उनकी स्थापना की तारीखें भी विवरण में दे दी गयी हैं।

(ख) इन शाखाओं को शीघ्रतापूर्वक खोलने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न तो किया जायगा परन्तु यह बताना सम्भव नहीं है कि ठीक किस किस तारीख को इनमें से प्रत्येक शाखा खुल सकेगी।

### Soft Coke Prices

948. **Shri I. Eacharan:** Will the Minister of Steel, Mines and Fuel be pleased to state:

(a) the controlled prices, fixed by the Central Government at which the colliery owners are allowed to sell soft coke to the State Governments and other consumers;

(b) the retail prices fixed for soft coke by various State Government; and

(c) the break up of retail prices of soft coke in respect of Delhi and Madras?

**The Minister of Steel Mines and Fuel (Sardar Swaran Singh):** (a) Rs. 28-75 np. per ton at the loading point nearest to the colliery and, is exclusive of Cess, Excise Duty, Labour Welfare Excise Duty, State Sales Tax etc.

(b) Retail prices of soft coke are fixed by respective State Governments from time to time and vary from district to district. Full information regarding all the States is not readily available and will take considerable time and labour to collect.

The following factors are generally taken into consideration in fixing the retail prices:

- (i) Railway freight.
- (ii) Central cesses and local taxes.
- (iii) Cartage, handling and other incidental charges including possible losses in transit.
- (iv) Middlemen's commission.
- (v) Dealer's profit.

(c) The break-up of the prices of soft coke on the basis of which the retail prices have been fixed in Delhi is as under:—

	Rs.
Pit head price . . . . .	26/12/- per ton.
Middlemen's commission . . . . .	1/8/- per ton
Railway freight . . . . .	17/5/6 per ton
Cess duty . . . . .	-12/2½ per ton
Terminal Tax . . . . .	-15/9 per ton
Unloading charges . . . . .	-9/6 per ton
Cartage . . . . .	2/8/- per ton
Stockagac . . . . .	-9/6 per ton
Pilferage . . . . .	-1/4 per ton
TOTAL . . . . .	51/1/9½ per ton
	OR
Profit for wholesalers . . . . .	1/15/6 per maund. -1/6 per maund.
Commission to retailer . . . . .	2/1/- wholesale rate -7/- per maund
TOTAL RETAIL PRICE . . . . .	2/8/- per maund.

In fixing the retail prices the above mentioned elements are generally taken into consideration by the other State Governments including that of Madras. Details regarding individual items in respect of Madras are not available.

### केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में भोजन की व्यवस्था

६४६. श्री लक्ष्मणराव राय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के कितने कार्यालयों में सरकार ने कर्मचारियों को प्रच्छा भोजन देने की व्यवस्था की है; और

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश कार्यालयों में ऐसी सुविधाएँ नहीं दी गई हैं जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को बाहर के खोचे वालों पर निर्भर रहना पड़ता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातर) : (क) केन्द्रीय सरकार के दिल्ली तथा नई दिल्ली स्थित लगभग सब कार्यालयों में भोजन की व्यवस्था कोपरेटिव/विभागीय केन्टीनों या टिफिन रूम के रूप में है। केन्टीन तथा टिफिन रूप में अन्तर यह है कि केन्टीन तो विभाग या सरकारी कर्मचारियों की कोपरेटिव सोसाइटी द्वारा बिना हानि लाभ के आधार पर चलाई जाती है जब कि टिफिन रूम प्राइवेट टेकेदारों द्वारा। टिफिन रूम की चीजों के दाम एंस्टेट आफिस द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) जी नहीं; जगह की कमी के कारण कुछ इमारतों में केन्टीन/टिफिन रूम की संख्या काफी नहीं है। इसलिए हो सकता है कि इन इमारतों में काम करने वाले, यदि अपने व्यक्तिगत स्वाद के लिए नहीं तो सम्भवतः केन्टीन अथवा टिफिन रूम की संख्या कम होने के कारण बाहर के खोचे

वालों या पटरी पर बैठ कर बेचने वालों से अपने खाने की चीजें खरीदते हो।

संयुक्त राष्ट्र आघात सेना के मुसलमान सैनिक

६५०. श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की आघात सेना के अधीन मिस्र में जो भारतीय सेना स्थित है उसमें से कितने मुसलमान सैनिकों ने इस वर्ष हज की यात्रा की ?

प्रतिरक्षा उपमंत्रो (सरदार मजीदिया) : एक।

### Grants to States for Scheduled Castes

951. Shri Nagi Reddy: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the total grant given to different States for the welfare of Scheduled Castes in 1956-57;

(b) the schemes for which the grants were made; and

(c) whether there is any proposal to set apart some amount for granting house sites to Scheduled Castes in the rural areas?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) Attention is invited to the reply given to part (a) of Swami Rama Nand Shastri's Unstarred Question No. 209 dated the 24th May, 1957

(b) The main heads of the schemes are:—

1. Propaganda & Publicity.
2. Education.
3. Agriculture and Cottage Industries.
4. Medical & Public Health including drinking water supply
5. Housing.
6. Aid to Voluntary agencies.